

[श्री हरनाथ सिंह यादव]

महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में तदर्थ व्यवस्थावाद के कारण प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक विद्यालयों को सवित्त मान्यताओं, नियमित शिक्षकों की भर्ती के स्थान पर संविदा पर निहायत अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती तथा वित्तविहीन मान्यताओं ने शैक्षिक वातावरण को बुरी तरह से दूषित कर दिया है।

महोदय, बीसियों साल से देश भर में अति अल्प वेतन अथवा मानदेय पर शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, प्रेरकों, तदर्थ शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों आदि के नाम से लाखों की संख्या में शिक्षक सेवारत हैं। जो सरकारी अथवा निजी विद्यालयों में तीन-चार हजार से दस-बारह हजार तक वेतन/मानदेय पर सेवा करने को विवश हैं।

महोदय, मेरी मांग है कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हुई तदर्थवादी/अल्पकालिक व्यवस्थाओं को रोकना चाहिए। शिक्षामित्र, अनुदेशक, प्रेरक, तदर्थ शिक्षक, विषय विशेषज्ञ आदि नामों से जाने वाले शिक्षकों को नियमित शिक्षक बनाने का मार्ग खोजना चाहिए तथा उन्हें मिलने वाला वेतन, भत्ता आदि समस्त सुविधाएं प्रदान करने पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। साथ ही विद्यालयों को वित्तविहीन मान्यता देने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस व्यवस्था को भी रोकना अपेक्षित है।

...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Shri T. Rathinavel, not present. Shri Sanjay Seth, not present.
Dr. Ashok Bajpai.

Demand to rejuvenate the textile industry in Kanpur

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): महोदय, एक समय में कानपुर एशिया का मानचेस्टर कहा जाता था। कानपुर में सैकड़ों कपड़ा उत्पादन की मिलें थीं और हजारों श्रमिक इन मिलों में काम करते थे। कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कहा जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद कपड़ा मिलों की स्थिति निरंतर दयनीय होती चली गई। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग धारीवाल और लाल इमली अपने उत्कृष्ट उत्पादन के कारण सारी दुनिया में अपनी पहचान बने हुए थे, परन्तु इन उद्योगों के बंद होने से हजारों श्रमिकों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। विश्व व्यापार संगठन समझौते के बाद यह आशा जगी थी कि कानपुर का वस्त्र उद्योग पुनर्जीवित हो सकेगा, लेकिन यह धारणा निर्मूल साबित हुई। निजी क्षेत्र के वस्त्र उद्योग तो बंद हो ही गए और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बंद होने से गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। प्रदेश की औद्योगिक उत्पादकता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सार्वजनिक उद्योग की कपड़ा मिलों के पास बहूमूल्य अचल संपदा है। बड़े भूभाग में फैले हुए इन उद्योगों की अतिरिक्त भूमि को बाजार मूल्य में बेचकर दुबारा पुनर्जीवित किए जा सकते हैं और उत्तर प्रदेश अपनी खोई हुई पहचान वापस ला सकता है। मैं लोक महत्व के इस अविलंबनीय प्रश्न को अपने माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि इस संबंध में कोई वृहत्तर कार्य योजना बनाई जाए, जिससे कि श्रमिकों के अंधकारमय भविष्य को संवारा जा सके और कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश अपनी महती भूमिका का निर्वाह कर सके।

...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Shri Motilal Vora, not present.

Demand to increase honorarium of Aanganwadi Workers

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): महोदय, देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को दिया जाने वाला मानदेय पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार के महत्वपूर्ण विशेष कामों में उनकी सेवाएं योजित की गई हैं, उसके अनुरूप मानदेय के बजाय उनकी आजीविका को सम्मानजनक चलाने के लिए वेतनमान और महंगाई भत्तों के साथ इस तरह के सरकारी कामों में कार्यरत लोगों के समान ही वेतन सुविधाएं निर्धारित की जाएं। केन्द्र तथा राज्य सरकारें इसके लिए शीघ्र समुचित प्रावधान कर, इनकी बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करें।

श्री सभापति: आप लोग बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए, प्लीज़ ...**(व्यवधान)**... रामदास जी, आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... जो आप कह रहे हैं, वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप मंत्री हैं, आपका कहना उचित भी नहीं है।

VALEDICTORY REMARKS

MR. CHAIRMAN: Members, as the monsoon session of Parliament concludes today, it is time for us to take stock of what this august House could do and could not during the session. Of the 18 scheduled sittings, the House decided to take leave on the occasion of Guru Purnima day and so, we had 17 sittings at our disposal. On another day, the House was adjourned for the day as a mark of respect to former Chief Minister of Tamil Nadu, late Dr. M. Karunanidhi after making obituary reference.

Going by the trend of the previous two sessions, the media forecast for this session had been that this too would be a washout with election fever setting in. I am glad and so would all of you that for once, media has been proved wrong. I compliment all of you for the same, though it is not to my full satisfaction.

South West monsoon is very critical for the economy of our country and it has been by and large normal with only about 5 per cent deficit in rainfall so far. And the Monsoon session of Parliament also brought new tidings marking a break from the last two sessions much to the delight of all those who have a stake in our Parliamentary democracy.

With productivity of more than 73 per cent, measured in terms of the functional time against the total time available, this session proved to be about three times more productive than the last budget session whose productivity was only about 25 per cent. This is a remarkable improvement and the credit goes to all of you. Still, I am not fully happy.